नईदुनिया



उत्पादों से नतीजों तक, ब्रांड्स के लिए बदल रहा है उपभोक्ता बाजार

सिंगापुर

मिंटेल के 2027 के वैश्विक अनुमान बताते हैं कि उपभोक्ता बाजार में ब्रांड ग्रोथ का तरीका बदल रहा है। अब सफलता सिर्फ नए उत्पाद लान्च करने पर नहीं, बल्कि कनेक्टेड सिस्टम के ज़रिए उपभोक्ताओं को उनके वांछित नतीजे (आउटकम) हासिल करने में मदद करने पर निर्भर करेगी।

ब्रांड्स को अब यह सोचना बंद करना होगा कि कौन सा उत्पाद लान्च किया जाए

यह बदलाव कैटेगरी की पुरानी सीमाओं को धुंधला कर रहा है और प्रतिस्पर्धा का माहौल बदल रहा है। मिंटेल ट्रेंड्स की एक अधिकारी के अनुसार ब्रांड्स को अब यह सोचना बंद करना होगा कि कौन सा उत्पाद लान्च किया जाए और यह पूछना शुरू करना होगा कि उनका ब्रांड उपभोक्ताओं को भरोसेमंद तरीके से क्या परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

उपभोक्ता अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादों, सेवाओं और व्यवहारों के मिश्रण का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक स्लीप ब्रांड अब सिर्फ़ दूसरे स्लीप उत्पादों से नहीं, बल्कि टेक्नोलाजी, न्यूट्रिशन या फ़िटनेस समाधानों से भी प्रतिस्पर्धा करेगा। यह बदलाव वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, ब्यूटी और घरेलू देखभाल जैसी बड़ी श्रेणियों को प्रभावित कर रहा है।

वेलनेस में रिकमेंडेशन इंजन नए प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं, जबकि फूड ब्रांड्स को सप्लीमेंट्स और टेक्नोलाजी से चुनौती मिल रही है। ब्यूटी में ग्राहक अब रूटीन के बड़े हिस्से के लिए सप्लीमेंट्स और डिवाइसेस पर खर्च कर रहे हैं, और घरेलू देखभाल में, घर के आटोमेटेड सिस्टम ब्रांड्स के लिए नई चुनौती पेश कर रहे हैं।

ब्रांड्स को यह समझना होगा कि उपभोक्ता क्या हासिल करना चाहते हैं और उन कनेक्टेड सिस्टम में अपनी एक स्पष्ट व भरोसेमंद भूमिका कैसे निभाएं। भविष्य में, हम टेक्नोलाजी, हेल्थकेयर और रिटेल क्षेत्रों में नई साझेदारियां देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जहाँ ब्रांड्स मिलकर उपभोक्ताओं के लिए बेहतर और एकीकृत समाधान पेश करेंगे।

न्यूज ब्रीफ

एप्पल कंपनी 10 दिसंबर को हैदराबाद में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलेगी



नई दिल्ली। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल 10 दिसंबर को हैदराबाद में अपना पहला रिटेल स्टोर खोलेगी। यह भारत में कंपनी का 7वां स्टोर होगा। कंपनी ने जानकारी दी कि 10 दिसंबर को शाम पांच बजे तेलंगाना के हैदराबाद में लेक शोर-वाई जंक्शन माल स्थित एप्पल कुकटपल्ली में खुलने वाला रिटेल स्टोर भारत में कंपनी का सातवां स्टोर होगा। ये स्टोर लेक शोर-वाई जंक्शन माल में खुलेगा और भारत में कंपनी का सातवां खुदरा स्टोर होगा। यह भारत में कंपनी के रिटेल कारोबार के विस्तार की दिशा में एक और उपलब्धि है। यह दक्षिण भारत में कंपनी की बढ़ती मौजूदगी को और मजबूत करेगा। देश में एप्पल का सातवां स्टोर होने के नाते यह हैदराबाद के ग्राहकों को कंपनी के उत्पादों को देखने और खरीदने के साथ-साथ उसकी सेवाओं और सहायता का प्रत्यक्ष अनुभव लेने के नए अवसर देगा। साइबर मीडिया रिसर्च की 2026 की तीसरी तिमाही में स्मार्टफोन की आपूर्ति पर जारी रिपोर्ट के अनुसार एप्पल भारत में सबसे अधिक बिकने वाले शीर्ष 5 ब्रांड में शामिल है। देश के स्मार्टफोन बाजार में इसकी हिस्सेदारी नौ फीसदी है। कंपनी ने कहा कि हैदराबाद में एप्पल की अनुसंधान एवं विकास और खुदरा ग्राहक सेवा टीम भी मौजूद हैं। एप्पल कुकटपल्ली स्टोर में कंपनी के नवीनतम आईफोन 18 प्रो और आईफोन 18 प्रो मैक्स, आईफोन डुओ, प्रोएलईडी एक्सडीआर डिस्प्ले और टच वाला मैकबुक प्रो, एप्पल वाच सीरीज 12 और अल्ट्रा 4 समेत सभी प्रमुख उत्पाद उपलब्ध होंगे।

उबर इंडिया-दक्षिण एशिया की कमान जोमैटो के पूर्व सीईओ राकेश रंजन को, 4 जनवरी 2027 से प्रभावी होगी नियुक्ति



नई दिल्ली। ऑनलाइन कैब बुकिंग मंच उबर ने भारत और दक्षिण एशिया के लिए अपनी नेतृत्व टीम में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। कंपनी ने जोमैटो के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) राकेश रंजन को इस क्षेत्र का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। रंजन की नियुक्ति 4 जनवरी, 2027 से प्रभावी होगी और वे उबर के एशिया प्रशांत क्षेत्र के महाप्रबंधक डोम टेलर को रिपोर्ट करेंगे। उबर से जुड़ने से पहले, रंजन शिक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी एलन ऑनलाइन के सीईओ थे। इससे पूर्व, उन्होंने जोमैटो में आठ साल तक काम किया, जहां उन्होंने खाद्य ऑर्डर और डिलीवरी कारोबार के सीईओ सहित कई नेतृत्वकारी जिम्मेदारियां संभाली थीं। डोम टेलर ने तीन माह से अधिक समय तक चली तलाश के बाद रंजन का स्वागत करते हुए कहा कि भारत और दक्षिण एशिया उबर के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। यात्राओं की संख्या के मामले में भारत, अमेरिका और ब्राजील के बाद उबर का तीसरा सबसे बड़ा बाजार है। साथ ही, मंच से कमाई करने वाले लोगों की संख्या के लिहाज से यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जो इसकी रणनीतिक अहमियत को दर्शाता है। रंजन ने इस जिम्मेदारी को भारत और दक्षिण एशिया में लोगों के आवागमन व कमाई के लिए अहम बताया।

आईसीएल फिनकॉर्प का 2,600 करोड़ रुपये का लोन बुक बनाने का लक्ष्य

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: केरल की एनबीएफसी कंपनी आईसीएल फिनकॉर्प लिमिटेड ने मार्च 2029 तक अपना नेट लोन बुक 2,600 करोड़ रुपये से अधिक करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी के प्रमोटरों ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 60 करोड़ रुपये की इक्विटी पूंजी निवेश की है, जिससे नेटवर्थ बढ़कर 242 करोड़ रुपये हो गई है। कंपनी दूसरी छमाही में 60 करोड़ रुपये और निवेश करने की योजना बना रही है। इसके अलावा एसबीआई से 125 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक से 200 करोड़ रुपये की बैंकिंग सुविधाएं मिली हैं। कंपनी एनसीडी के माध्यम से 500 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। वर्तमान में 13 राज्यों में इसकी लगभग 300 शाखाएं हैं। कंपनी का एयूएम बढ़कर 1,235 करोड़ रुपये हो गया है।

भारतीय चीनी को मिला अमेरिकी बाजार, 8,606 टन निर्यात को हरी झंडी

अमेरिका के संभावित शुल्क के बावजूद भारतीय निर्यातकों को मिलेगा लाभ



नई दिल्ली

भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अमेरिकी बाजार में 8,606 टन कच्ची चीनी के निर्यात को मंजूरी दे दी है। यह निर्यात कोटा 1 अक्टूबर 2026 से 30 सितंबर 2027 तक की अवधि के लिए वैध होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा इस संबंध में जारी एक आदेश के अनुसार, यह निर्णय टैरिफ रेट कोटा (योजना के तहत लिया गया है, जो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ दिलाएगा। टीआरक्यू योजना के तहत एक निश्चित मात्रा तक के सामान पर आयात शुल्क या तो शून्य होता है या काफी कम दर पर लगाया जाता है। यह प्रावधान भारतीय चीनी को अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए अधिक आकर्षक बनाएगा, खासकर ऐसे समय में जब कुछ राजनीतिक जानकारों के अनुसार अमेरिकी प्रशासन भारत सहित विभिन्न देशों पर फिर से आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रहा है। इसके बावजूद, यह कदम भारतीय चीनी को अमेरिकी बाजार में मिठास घोलने का अवसर देगा। निर्धारित 8,606 टन की मात्रा मीट्रिक टन रा वैल्यू में तय की गई है, जो अंतरराष्ट्रीय चीनी व्यापार में कच्ची चीनी के वजन मापने का एक मानक है। इस निर्यात के लिए मूल देश का प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट आफ ओरिजिन) अनिवार्य होगा, जिसे मुंबई स्थित विदेश व्यापार महानिदेशालय का अतिरिक्त महानिदेशक जारी करेगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपेडा) इस पूरी प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। एपेडा ही संबंधित कंपनियों और निर्यात की मात्रा की सिफारिश करेगा, जिसके आधार पर आवश्यक दस्तावेज जारी किए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि सरकार का यह कदम भारतीय चीनी उद्योग के लिए अमेरिकी बाजार में नए अवसर खोलेगा और भारत व अमेरिका के बीच कृषि उत्पादों के व्यापारिक संबंधों को मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि यह एक वर्ष के लिए निर्धारित कोटे के तहत सीमित निर्यात है, लेकिन यह दोनों देशों के बीच निरंतर व्यापारिक सहयोग का स्पष्ट संकेत है।

फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति पद छोड़ने को तैयार, दस साल बाद कमान छोड़ेंगे कृष्णमूर्ति, आपातकालीन टाउनहाल बैठक बुलाई गई



नई दिल्ली। वालमार्ट के स्वामित्व वाली ई-कामर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट में एक बड़ा नेतृत्व परिवर्तन होने जा रहा है। करीब दस साल तक कंपनी की कमान संभालने वाले सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति अगले कुछ हफ्तों में अपना पद छोड़ने की तैयारी में हैं। सूत्रों के अनुसार इस महत्वपूर्ण बदलाव पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन टाउनहाल मीटिंग बुलाई गई है, जिससे स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। कृष्णमूर्ति ने 2017 में सीईओ का पद संभाला था और संस्थापकों के जाने के बाद पिछले एक दशक में उन्होंने फ्लिपकार्ट को स्थिरता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में कंपनी ने भारतीय ई-कामर्स बाजार में अमेजन और मीशो जैसे प्रतिद्वंद्वियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना किया, साथ ही फ्लिपकार्ट मिनट्स जैसी क्विक कामर्स सेवाओं और जेन-जेड ग्राहकों के लिए नए उत्पाद क्षेत्रों में विस्तार किया। हालांकि, उनका यह कदम ऐसे समय में आया है जब फ्लिपकार्ट आंतरिक चुनौतियों से जूझ रही है, जिनमें कंपनी के आईपीओ में देरी, फंड जुटाने की कोशिशें और वरिष्ठ अधिकारियों का लगातार कंपनी छोड़ना शामिल है। आईपीओ में देरी से कर्मचारियों के ईएसओपी लाभों को लेकर भी असंतोष बढ़ा है। जानकारों के मुताबिक, पिछले एक साल में कम से कम 14 उपाध्यक्ष और वरिष्ठ उपाध्यक्ष फ्लिपकार्ट छोड़ चुके हैं, जो कंपनी के मनोबल पर असर डाल रहा है।

एन चंद्रशेखरन की तीसरी बार नियुक्ति के खिलाफ बाम्बे हाई कोर्ट पहुंचा टाटा ट्रस्ट



नई दिल्ली

सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) और आरडी टाटा ट्रस्ट (आरडीटीटी) ने बाम्बे हाई कोर्ट में टाटा संस और उसके 6 निदेशकों के खिलाफ मुकदमे दायर किए हैं। हाई कोर्ट की एकल पीठ शुक्रवार को इन मुकदमों पर सुनवाई कर सकती है।

कोर्ट में टाटा ट्रस्ट की ओर से दायर मुकदमों के अनुसार एन. चंद्रशेखरन को दोबारा नियुक्त करने के लिए टाटा संस के निदेशक मंडल की 17 सितंबर का पारित प्रस्ताव अमान्य था। ट्रस्ट ने कहा कि इसे कंपनी के अंतर्नियमों (एओए) के अनुच्छेद 121 के तहत जरूरी समर्थन में मत नहीं मिला था। दोनों ट्रस्ट ने एन. चंद्रशेखरन को कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में तीसरे पांच साल के कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त किए जाने को लेकर चुनौती दी है। एसडीटीटी ने 50 करोड़ रुपये और आरडीटीटी ने 15 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है। दोनों ट्रस्ट ने इस राशि पर सालाना 18 फीसदी ब्याज भी मांगा है। ट्रस्ट ने तत्काल राहत के तौर पर यह मांग की है कि 30 नवंबर को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में नामित निदेशकों के बीच मतभेद की स्थिति में टाटा संस के चेयरमैन अपने निर्णायक मताधिकार का इस्तेमाल न कर सकें।

यह विवाद 17 सितंबर को निदेशक मंडल की बैठक में चंद्रशेखरन को टाटा संस का कार्यकारी चेयरमैन अगले पांच साल के लिए फिर से नियुक्त किए जाने के बाद शुरू हुआ। इससे पहले दोनों ट्रस्ट ने हाई कोर्ट जाने के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। उनका कहना है कि 17 सितंबर के बाद से इस मामले में भेजे गए पत्रों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। नोएल टाटा की अध्यक्षता वाले टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी हिस्सेदारी है। ट्रस्ट ने 17 सितंबर को पारित निदेशक मंडल के प्रस्ताव को चुनौती दी है। ट्रस्ट ने 20 सितंबर को जारी एक बयान में कहा था कि यह प्रस्ताव वैध रूप से पारित नहीं हुआ और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है।

केरल में यूडीएफ ने नई आबकारी नीति हेतु उपसमिति बनाई



तिरुवनंतपुरम । केरल में सत्तारूढ़ संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने राज्य की नई आबकारी नीति पर चर्चा और सिफारिशें देने के लिए एक उपसमिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार पूर्व विधायक के. शिवदासन नायर इसके संयोजक होंगे। समिति में पीजे जाय, जाय अब्राहम, विधायक के जयंथ, विष्णु मोहन, वक्कनाड राधाकृष्णन और सीए अजीर सदस्य हैं। यह कदम तब उठाया गया है जब कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की आबकारी नीति को बदलकर नई नीति लाना चाहती है। आबकारी मंत्री एम. लिजू ने संकेत दिया था कि चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं और सरकार नवंबर अंत तक इसकी घोषणा का लक्ष्य लेकर चल रही है।

भारतीय बैंकों की ऋण वृद्धि 2027 में भी दोहरे अंक में रहने का अनुमान: फिच

मार्च 2028 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2027-28 में भारतीय बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन स्थिर रहेगा



नई दिल्ली

विश्व की प्रमुख रेटिंग्स एजेंसी फिच ने कहा कि भारतीय बैंकों की ऋण वृद्धि 2027 में भी दोहरे अंक में रहने की उम्मीद है। वहीं लागत दक्षता में सुधार से उनकी लाभप्रदता बढ़ेगी और पूंजी पर्याप्तता स्थिर बनी रहेगी। फिच को उम्मीद है कि मार्च 2028 में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष 2027-28 में भारतीय बैंकों का वित्तीय प्रदर्शन स्थिर रहेगा। मजबूत आर्थिक वृद्धि से ऋण वृद्धि करीब 15 प्रतिशत बनी रहेगी, जबकि नीतिगत ब्याज दर में मामूली बढ़ोतरी से शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) और आय को समर्थन मिलेगा। एशिया-प्रशांत क्षेत्र के बैंकों पर जारी अपनी रिपोर्ट में फिच ने कह कि कर्ज की अवधि बढ़ने के साथ परिसंपत्तियों की गुणवत्ता पर दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन कर्ज की वसूली और बट्टे खाते में डाले जाने वाले कर्ज से इसका असर कम हो जाएगा। ऋण वृद्धि और लागत दक्षता में सुधार से लाभप्रदता को समर्थन मिलेगा और पूंजी पर्याप्तता स्थिर बनी रहेगी। फिच के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में कुछ क्षेत्रों में कर्ज की तेज वृद्धि के कारण नए गैर-निष्पादित ऋण (एनपीएल) के मामले मामूली रूप से बढ़ सकते हैं। इनमें बिना गारंटी वाले व्यक्तिगत ऋण और कृषि कारोबार से जुड़े कर्ज शामिल हैं, जो बाहरी परिस्थितियों में बदलाव के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। फिच ने अनुमान जताया कि वित्त वर्ष 2027-28 में ऋण लागत बढ़कर कुल कर्ज के करीब 0.8 प्रतिशत पर पहुंच सकती है, जो वित्त वर्ष 2026-27 में अनुमानित 0.6 प्रतिशत है। हालांकि, वित्त वर्ष 2027-28 में एनपीएल अनुपात दो प्रतिशत से नीचे रहने की संभावना है।

नए श्रम कानून एक साल बाद भी कंपनियों में पूरी तरह से नहीं हुए लागू: रिपोर्ट

सर्वे का खुलासा: वेतन, पीएफ और ग्रेच्युटी में बढ़ोतरी से कंपनियों पर बढ़ेगा बोझ



नई दिल्ली

कर्मचारियों और मजदूरों की भलाई के लिए देश में बीते साल लागू किए गए चार नए श्रम कानूनों को कंपनियां पूरी तरह से अपनाने में अभी भी पीछे हैं। एक ताजा सर्वे रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि एक साल बीत जाने के बाद भी आधी से अधिक कंपनियां इन नियमों को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं, जिसका मुख्य कारण वेतन संरचना और पेरोल सिस्टम में आने वाले बदलाव हैं। सर्वे के अनुसार केवल 50.6 फीसदी कंपनियों ने ही इन कानूनों को लागू करने की तैयारी पूरी की है, जबकि 28.8 फीसदी अभी इस प्रक्रिया में हैं। चिंताजनक बात यह है कि 11.7 फीसदी कंपनियों ने तो इस दिशा में काम ही शुरू नहीं किया है और 9 फीसदी को तो इन बदलावों की जानकारी तक नहीं है। यानी, लगभग आधी कंपनियां अभी भी नए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने से दूर हैं। नए श्रम कानूनों से कंपनियों पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका है। 74.4 फीसदी कंपनियों ने माना है कि नए वेतन नियमों से उनका खर्च बढ़ेगा, जिसमें से 49.6 फीसदी का अनुमान है कि यह खर्च 5 फीसदी तक बढ़ सकता है।

60 टन सोना विदेशों से भारत वापस, देश में सुरक्षित हुआ 84 फीसदी भंडार

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पिछले छह महीनों में लगभग 60 टन सोना विदेशों से भारत वापस मंगाया है। इस कदम से अब आरबीआई के कुल स्वर्ण भंडार का 84 फीसदी हिस्सा देश के भीतर ही सुरक्षित हो गया है, जो पहले 77 फीसदी से थोड़ा अधिक था। यह कदम वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता के बीच भारत के स्वर्ण भंडार की सुरक्षा और उस पर बेहतर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मार्च से सितंबर 2026 के दौरान 60.08 टन सोना भारत लाया गया। सितंबर 2026 के अंत तक आरबीआई के पास कुल 880.52 टन सोना था, जिसमें से 740.13 टन अब देश में ही सुरक्षित है। यह उल्लेखनीय है कि यह स्थानांतरण कुल स्वर्ण भंडार में बढ़ोतरी नहीं करता, बल्कि विदेशों में रखे सोने से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए किया गया है। दुनिया भर में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध और आर्थिक अस्थिरता के मौजूदा माहौल में, आरबीआई अपने मूल्यवान स्वर्ण रिजर्व को देश में ही सुरक्षित रखना चाहता है ताकि किसी भी आपात स्थिति में उस पर तत्काल और आसानी से नियंत्रण किया जा सके। यह कदम भारत की आर्थिक संप्रभुता और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल मानी जा रही है।